THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Recently, Consumer Protection Act, 1986 has been amended to empower the State Governments/UT Administrations to set up more than one District Forum wherever considered necessary, depending upon the workload. The decision to set up more than one District Forum, now, rests exclusively with State Governments/UT Administrations. The Government of National Capital Territory of Delhi has so far established two District Forums in Delhi.

आई०एस०आई० चिन्ह् के लिए लाईसेंस जारी करने में भ्रष्टाचार

246. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी**: क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आई० एस० आई० चिह्न के लिए लाइसेंस जारी करने में बड़े पैमाने पर धांधलेबाजी और भ्रष्टाचार हो रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय मानक ब्यूरो (बी० आई० एस०) के अधिकारी और कर्मचारी इन कृत्यों में संलिप्त है जिनके कारण ऐसे काले कारनामों को बढ़ावा मिल रहा है और इस उच्च संस्थान की विश्वसनीयता कम हो रही है; और

(ग) सरकार को इस संस्थान के विरुद्ध अब तक कितनी शिकायतें मिली हैं और क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में अब स्थित कार्यालयों में मात्र खानापूर्ति की जा रही है और प्रत्येक वस्तु का कड़ाई से निरीक्षण करने के मामले में लापरवाही बरतने के लिए कितने कर्मचारी दोषी पाए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय मानक ब्यूरो में भ्रष्टाचार के संबंध में समय-समय पर कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यह कहना सच नहीं है कि विभिन्न राज्यों में स्थित भारतीय मानक ब्यूरो के क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में भारतीय मानक ब्यूरो लाइसेंसों की मंजूरी और उनके संचालन कार्य में केवल औपचारिकताओं का पालन किया जा रहा है। गत 5 वर्षों के दौरान एक अधिकारी को दोषी पाया गया और उसे भारतीय मानक ब्यूरो लाइसेंस के संचालन कार्य के संबंध में कदाचार के कारण दण्डित किया गया है। इसके अतिरिक्त, चार अन्य अधिकारियों को अन्य कदाचारों के कारण दोषी पाया गया और दंडित किया गया है।

Employment on compassionate grounds in Super Bazar

247. SHRI GOPAL SINGH G. SOLANKI: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) the number of applications received in Super Bazar for compassionate employment during each of the last three years, year wise;

(b) the number of applications granted and rejected, separately;

(c) the reasons for granting some and rejecting others;

(d) what steps Government propose to take to give compassionate employment in all cases where it is on account of death of serving employees; and

(e) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION AND THE MINISTER OF